CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

मध्य प्रदेश सरकार बकरी के दूध को 30 रुपये प्रति 200 मिली पर बेचना शुरू करेगी

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़वानी से 'जनजाति गौरव दिवस' पर बकरी के दूध की बिक्री शुरू की। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि इससे गरीबों को कमाई के मौके मिलेंगे। प्रथम चरण में जबलपुर एवं इंदौर संभाग के आदिवासी बहुल जिलों से एकत्रित बकरी के दूध को एकत्रित कर बेचा जाएगा।

इंदौर संभाग में धार, झाबुआ और बड़वानी में आदिवासियों से बकरी का दूध खरीदा जाएगा जबकि जबलपुर संभाग में सिवनी और बालाघाट जिलों में आदिवासियों से दूध खरीदा जाएगा। सरकार इसे 50 रुपये से 70 रुपये प्रति लीटर के प्राइस रेंज में खरीद रही है। इंदौर और जबलपुर दुग्ध संघ इसकी एजेंसियां हैं। यह दूध पार्लर में अधिकतम 30 रुपये प्रति 200 मिलीलीटर की बोतल के साथ उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि बकरी के दूध में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जस्ता में समृद्ध है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

बनास डेयरी ने बनासकांठा में सैनिक स्कूल खोलने की मांगी मंजूरी

बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जो उत्तरी गुजरात में बनास डेयरी का संचालन करती है, ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को राज्य में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। “हमने लगभग 15 दिन पहले रक्षा मंत्रालय को एक आवेदन दिया है। बनास डेयरी द्वारा संचालित गलभाभाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। डेयरी और ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य एक ही हैं" बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने बताया।

बनास डेयरी ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और पालनपुर के पास जमीन की तलाश कर रही है। “हम शुरू में प्रत्येक कक्षा में 50 की ताकत के साथ कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों को नामांकित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार की नीति में बदलाव के साथ, हम लड़के और लड़कियों दोनों का नामांकन करेंगे,” चौधरी ने कहा कि यह ऐसे 100 स्कूलों में से एक होगा, जिसे भारत सरकार ने अक्टूबर में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत देश भर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

स्टेलैप्स टेक ने जीता 'डिजिटल इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्ट-अप' का पुरस्कार

स्टेलैप्स टेक्नोलॉजीज को भारत में डेयरी क्षेत्र को डिजिटल बनाने के प्रयास के लिए एग्री-फूड एम्पॉवरिंग इंडिया अवार्ड्स में 'डिजिटल नवाचारों में सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्ट-अप' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और नवीन अवधारणाओं को मान्यता देता है।

स्टेलैप्स को डेयरी फार्मिंग प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने और मजबूत करने में अपने नवीन तकनीकी समाधानों के लिए पहचाना गया है। स्टेलेप्स के सीईओ और सह-संस्थापक रंजीत मुकंदन ने कहा, "हम एग्री-फूड एम्पॉवरिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में 'डिजिटल इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्ट-अप' प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह पुरस्कार भारत में डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों की स्वीकृति है और इसने हमें बहुत खुशी और प्रेरणा दी है। हमारा लक्ष्य भारत में कृषि विकास में योगदान देना और अपने अभिनव समाधानों के माध्यम से छोटे किसानों के सशक्तिकरण में योगदान देना है।

सरकार ने पशुधन, डेयरी, मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया

केंद्र ने सोमवार को देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया और अगले तीन महीनों में लगभग दो करोड़ लोगों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने वस्तुतः 15 नवंबर, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक 'राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान' शुरू किया। बजट 2018-19 में, सरकार ने पशुपालन किसानों और मछुआरों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी सुविधा के विस्तार की घोषणा की थी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य किसानों को केसीसी प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें संस्थागत ऋण मिले। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पशुपालन और डेयरी विभाग के अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र तीन महीने के अभियान के दौरान लगभग दो करोड़ पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य किसानों को केसीसी प्रदान करने का लक्ष्य बना रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि किसान बिना किसी जमानत के केसीसी पर 1.6 लाख रुपये की ऋण सीमा प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालन विभाग के सचिव जतिंद्र नाथ स्वैन ने कहा कि इस अभियान में करीब 50 लाख मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने बुधवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लाभार्थियों को डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्र की स्थापना में ऋण सहायता प्रदान करके विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

एमओयू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डीएएचडी को आय सृजन, ग्रामीण गरीबों के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने की सुविधा प्रदान करेगा, जब भी उन्हें गुणवत्ता नियंत्रण की स्थापना/विस्तार/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभों के विस्तार के माध्यम से, डेयरी प्रसंस्करण और इसके मूल्यवर्धन, मांस प्रसंस्करण, और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचे, पशु चारा संयंत्र और प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त नस्ल सुधार फार्म बिना किसी सीमा के।

एमओयू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डीएएचडी दोनों की पुष्टि करेगा ताकि लाभार्थियों को पीएम किसान संपदा योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिककरण और डीएएचडी की डेयरी विकास योजनाओं के तहत लाभ मिल सके। यह न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डीएएचडी के लाभार्थियों को सशक्त करेगा, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में उनकी संबंधित कार्यान्वयन सहायता टीम के माध्यम से जागरूकता भी पैदा करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डीएएचडी के बीच अभिसरण लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधा के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन, डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, और पशु चारा आदि शामिल हैं।

स्टार्ट-अप: डेयरी-केंद्रित नियो-बैंक डीजीवी को पहली संस्थागत फंडिंग में 3.1 मिलियन डॉलर मिले

डिजीवृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (डीजीवी), एक डेयरी उद्योग केंद्रित नियो-बैंकिंग स्टार्ट-अप ने इंफो एज वेंचर्स और ओमनिवोर से प्री-सीरीज़-ए राउंड में 3.1 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। अपने सहायक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डीजीवी डेयरी किसानों को औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर रहा है। डीजीवी वर्तमान में कुछ सहकारी डेयरी संघों और उनकी संबंधित दूध सहकारी समितियों और किसानों के साथ काम कर रहा है, उन्हें फेडरल बैंक के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से भुगतान, देनदारियों और परिसंपत्ति उत्पादों तक पहुंच प्रदान करके। डीजीवी की स्थापना 2019 में रागवन वेंकटेशन द्वारा की गई थी, जो पहले IDFC बैंक और NPCI दोनों में संस्थापक टीम का हिस्सा थे। डीजीवी के वरिष्ठ प्रबंधन में मुकेश रंजन, पूर्व रुपे कार्ड योजना और जियो पेमेंट्स के संस्थापक सदस्य, रवि सिंह, पूर्व एनपीसीआई एचआर लीड और वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज के पूर्व बिजनेस लीड सौरभ मेहता शामिल हैं।

"हम अपने पहले संस्थागत दौर का नेतृत्व करने के लिए इंफो एज वेंचर्स और ओमनिवोर का स्वागत करते हुए प्रसन्न हैं। डिजिटल मार्केटप्लेस के विस्तार में इंफो एज वेंचर्स का अनुभव, और एग्रीटेक में ओमनिवोर का गहरा अनुभव, हमें डेयरी किसानों के लिए एक पूर्ण-सेवा मंच बनाने की अनुमति देगा, "रागवन वेंकटेशन, संस्थापक और सीईओ, डीजीवी ने कहा।

इंफो एज वेंचर्स के पार्टनर किट्टी अग्रवाल ने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग 145 अरब डॉलर के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डेयरी बाजार है, जिसमें 75 मिलियन से अधिक डेयरी किसान शामिल हैं। "इस उद्योग के विशाल आकार और हमारी आजीविका के लिए इसके महत्व के बावजूद, डेयरी किसानों के पास बुनियादी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच नहीं है और यहां तक कि आसानी से नकदी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। DGV इन किसानों के लिए क्रेडिट, बीमा और अन्य जरूरतों के लिए अनुकूलित विभिन्न वित्तीय उत्पादों के निर्माण की योजना के साथ आधार, राष्ट्रीय भुगतान स्विच और माइक्रो एटीएम तकनीक का उपयोग करके पूरे भुगतान स्टैक को डिजिटाइज़ करके इन डेयरी किसानों के लिए एक नव-बैंकिंग मंच का निर्माण कर रहा है। हम राघवन के साथ साझेदारी करके बहुत उत्साहित हैं, जो इन डेयरी किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके लिए आवश्यक वित्तीय समावेशन लाने के लिए बेहद भावुक हैं।

MAITRIs के दूसरे बैच को भटिंडा में प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू, डॉ. सागर डी. डोईफोड ने यहाँ पशुधन विकास बोर्ड कार्यालय परिसर बेलीचरण से आज कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भटिंडा (पंजाब) में तीन महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 47 मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन) के दूसरे बैच को झंडी दिखाकर रवाना किया। ।

MAITRIs की स्थापना 'गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के गोजातीय प्रजनन घटक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की गई है। MAITRIs बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होंगे, उनके प्राथमिक कार्य यानी कृत्रिम गर्भाधान के साथ वे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य महत्वपूर्ण संबद्ध कार्य भी करेंगे जैसे पशु चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, राष्ट्रीय डेटाबेस में डेटा प्रविष्टि, दूध रिकॉर्डिंग, चारा बीज का वितरण, पशुधन बीमा आदि।

निदेशक ने आगे कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, MAITRIs को विभिन्न एआई इनपुट के साथ-साथ पशुधन विकास बोर्ड जम्मू द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए मौद्रिक सहायता के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।